भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 196
जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2022/28 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया जाना है

बजट में तेल की कीमतों पर रूस-यूक्रेन संकट का प्रभाव

196. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:
श्री राजमणि पटेल:
श्रीमती फूलो देवी नेताम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट इस गणना के आधार पर निर्धारित किया गया था कि अप्रैल से कच्चे तेल की अनुमानित कीमतें 75 अमेरिकी डॉलर से 80 अमेरिकी डॉलर के बीच रहेंगी;
(ख) यदि हाँ, तो कच्चे तेल की कीमतों में मौजूदा उछाल का बजट पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, इसका ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार कच्चे तेल की कीमतों में मौजूदा उछाल की प्रतिक्रिया में बजट के किसी हिस्से में संशोधन करने का इरादा रखती है; और
(घ) क्या सरकार का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ेगा, यदि हां, तो क्या सरकार ने सीएडी को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): जी, नहीं। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में कच्चे तेल के किसी विशेष मूल्य स्तर का अनुमान नहीं लगाया गया है। बजट एलपीजी को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। एलपीजी के लिए उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और दूर-दराज के क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए निर्धारित दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में कच्चे तेल की कीमतें 70 अमरीकी डॉलर से 75 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल के बीच होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वास्तविक रूप में 8% से 8.5% रहने का अनुमान है।

(घ): भारत के चालू खाता घाटे (सीएडी) का आकार कच्चे तेल की कीमत सहित कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात, आयात, कच्चे तेल की कीमत शामिल है। सरकार सीएडी की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रही है और हाल ही में सोने के आयात को नियंत्रित करने के लिए सोने पर सीमा शुल्क 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया है जिससे सीएडी कम होने की संभावना है।

*****